'वक्त आ गया है, जब बुजुर्ग नेताओं को नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए'

आचार्य प्रमोद ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करते हुए कहा अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाएं

जयपुर, (का.प्र.)। सचिन पायलट की तारीफ़ हज़्म नहीं हुई अचानक फ़ूड पोईजिनिंग शुरू हो गयी। यह ट्वीट करने वाले कांग्रेस नेता व प्रियंका गांधी के नजदीकी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही कोल्डवार में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करते हुए कहा है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता यह मानती है कि 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और बड़े नेताओं ने आपसी सलाह से फैसला लिया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत को मुखिया बनाया जाएगा। अब वक्त आ गया है, जब बुजुर्ग नेताओं को नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए।

प्रमोद कृष्णम ने इससे आगे कहा कि यह सृष्टि का नियम है, जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। एक साइकलिंग है। युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, यह तो हमेशा कांग्रेस की की आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। खुद अशोक गहलोत ने कहा था कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं। वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी जो फाइट है 2024 की वो पूरे देश को बचाने की है। 2024 की इस लड़ाई में गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए। पूरे देश को मोबलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबेलाइज करने के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने चाहिए।

> ■ 'गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर आकर पूरे देश को मोबलाइज करने के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने चाहिए'

प्रमोद कृष्णम सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति हैं। उन्हें कोई गाली भी देता है तो आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। पायलट बहुत होनहार व्यक्ति हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। जहां तक गुटों की बात है, समर्थकों की बात है तो कांग्रेस का नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके बाद पार्टी का एक-एक विधायक एक-एक कार्यकर्ता उस फैसले का सम्मान करेगा। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वरना देश खतरे में है। कांग्रेस कैसे मजबूत हो। कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम युवाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस तब मजबूत होगी जब सचिन पायलट जैसे युवा का सम्मान होगा।

गौरतलब है कि शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में मीडिया से बात करते हुए 2020 में कांग्रेस की बगावत को लेकर सचिन पायलट पर निशाना साधा था। सोमवार को सचिन पायलट ने टोंक दौरे पर संयमित भाषा में मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब दिया था। अब इस कोल्ड वार को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट की ताजपोशी की मांग आगे बढ़ाते हुए गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में डाल दी है।

ई.आर.सी.पी. पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे सीएम : शेखावत

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सांसदों एवं विधायकों की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी मौजूद रहे।

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सांसदों एवं विधायकों की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने संबोधित किया।

> ■ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने राजस्थान सरकार को घेरा
>
> ■ बोले, ''जनता के हितों के प्रति यदि किसी ने पाप किया है तो वह गहलोत ने किया है''

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए शेखावत ने कहा कि राजस्थान और इन 13 जिलों की जनता के हितों के प्रति यदि किसी ने पाप किया है तो वह गहलोत ने किया है। मुख्यमंत्री इस पाप को कहीं भी जाकर धोएंगे तो उनके पाप नहीं धुलेंगे।

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ईआरसीपी के विषय में भाजपा कार्यालय में पूर्वी राजस्थान के पार्टी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्हें समस्त तकनीकी व व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराया और रायशुमारी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को राजस्थान सरकार की भांति राजनीतिक प्रयोग की विषयवस्तु नहीं मानती। हम योजना के हर पहलू को जनहित के आधार पर गंभीरता से परखते हैं।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ईआरसीपी को राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लेना चाहती है। इन 13 जिलों नहीं, अपितु पूरे राजस्थान में जिस तरह की भ्रांति पैदा करने का प्रयास गहलोत की सरकार ने किया है, खुद गहलोत ने खुद किया है। शेखावत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में राज्य की करीब 40 प्रतिशत आबादी रहती है। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से ईआरसीपी परियोजना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार परियोजना पर राज्य सरकार को हर संभव मदद देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अर्नगल बातें बनाकर परियोजना को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत, जबकि 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को खर्च करनी होती है। केंद्र सरकार इससे भी आगे जाकर इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कैसे प्राप्त हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है, पर विकास की इस परियोजना को मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक हथियार बनाए जाने से लोग इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीपी परियोजना को लेकर चल रहे गतिरोध के संबंध में शेखावत ने कहा कि जिस तरह की मंशा को लेकर अशोक गहलोत सरकार इस परियोजना को लागू करना चाहती है, उस पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार आपत्ति दर्ज करा चुकी है, लेकिन गहलोत सरकार उन तथ्यों पर लगातार पर्दा डालते हुए केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के प्रावधानों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले चरण में सीडब्ल्यूसी द्वारा तकनीकी स्वीकृति तभी दी जाती है, जब परियोजना को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 75 प्रतिशत निर्भरता पर नियोजित किया गया हो।

गहलोत के शासन में हिन्दू कहीं भी सुरक्षित नहीं : डॉ. सतीश पूनिया

> ■ भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में बनाई रणनीति, आगामी दिनों में राजस्थान बंद की संभावना
>
> ■ यह वारदात सभ्य समाज को भयग्रस्त करने की साजिश का हिस्सा है, गहलोतजी सपाटबयानी कर पल्ला नहीं झाड़ सकती है : गजेंद्र सिंह शेखावत

जयपुर। उदयपुर में निर्मम हत्या मामला के मामले में भाजपा नेताओं ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। उदयपुर के मामले को लेकर भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी हुई। इसमें इस मामले को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। आगामी दिनों में भाजपा राजस्थान बंद की तैयारी भी कर सकती हैं।

इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ जासूसी के लिए पुलिस का उपयोग होता है। राजस्थान सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। पीएफआई को संरक्षक कौन दे रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उदयपुर की जनता के साथ भाजपा खड़ी है। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार के आने के बाद तुष्टिकरण घटना बढ़ीं। पीएफआई को अनुमति, रामनवमी पर धारा 144 होती है। 17 जून को खुलेआम धमकी दी थी, मृतक ने सुरक्षा मांगी थी। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री किस तरह से आतंवादियों पर कार्रवाई होगी। ये हमला समग्र हिंदू समाज पर हमला है। उदयपुर में आज की घटना यह प्रमाणित करती है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत के शासन में हिन्दू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति का ही परिणाम है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और क़ानून का भय समाप्त हो गया है।

नेता गुलाबचंद कटारिया जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना हो गए उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करें वरना उदयपुर बंद होगा। आरोपियों ने 17 तारीख की धमकी का वीडियो बनाया था। उसके बाद हत्या कर वीडियो वायरल किया। इस मामले में पूरी गैंग शामिल होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार की शह के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और प्रदेश में साम्प्रदायिक उन्माद व हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपराधी इतने बैखोफ हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर हिंसक बयान दिया है। घटना में लिप्त सभी अपराधियों की तुरंत गिरफ़्तारी हो और कड़ी सजा मिले। इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन्हें भी राज्य सरकार बेनक़ाब कर गिरफ़्तार करे।

डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश की इस्लामपरस्त अशोक गहलोत सरकार की हिन्दू विरोधी नीतियों का खामियाजा आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। उदयपुर में घटी जघन्य घटना न केवल निंदनीय है बल्कि असहनीय भी है। कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति ने आज कन्हैयालाल के प्राण ले लिए। पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि उदयपुर के एक सीधे-सादे नागरिक की बर्बरता से हत्या और आरोपियों द्वारा वीडियो बनाकर अपराध स्वीकारना बताता है कि तुष्टिकरण सीमाएं लांघ जाए तो वातावरण खूनी वैमनस्य का शिकार हो जाता है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत को अनदेखा किया, जिसका वीभत्स परिणाम सामने है। यह वारदात सभ्य समाज को भयग्रस्त करने की साजिश का हिस्सा है, गहलोतजी सपाटबयानी कर पल्ला नहीं झाड़ सकती है। उनकी जिम्मेदारी है प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना और उन कारणों पर रोक लगाना जिनसे इस तर्ज के अपराध और अपराधी पनप रहे हैं। अपनी एकांगी नीतियों की वजह से राज्य सरकार वैसे भी कटघरे में खड़ी है।

'डीसी को जानकारी ही नहीं किस शपथ पत्र पर साइन कर रहे हैं'

जयपुर। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने भूमि अवाप्ति के मुआवजे से जुड़े मामले में तत्कालीन जोन उपायुक्त की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अधिकरण ने कहा है कि प्रभारी अधिकारी ने जवाब पर हस्ताक्षर करने के अलावा अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। तत्कालीन जोन 11 के उपायुक्त अशोक योगी को यह भी जानकारी नहीं थी कि अधिकरण में पेश किया गया शपथ पत्र किस उद्देश्य के लिए था।

अधिकरण ने कहा कि किसी भी प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति इस उद्देश्य से की जाती है कि वह प्रकरण दर्ज होने के बाद से उसके निस्तारण तक हर स्टेज पर अपडेट रहे और अपने वकील को मार्गदर्शन दे, लेकिन सेज जैसी महत्वपूर्ण योजना में 25 फीसदी भूमि के आवंटन के इस गंभीर मामले में तत्कालीन उपायुक्त ने कोई रूचि नहीं ली। इसके अलावा न तो जवाब पेश किया गया और ना ही सही शपथ पत्र पेश किया गया। उनका यह कृत्य मिसकंडट को दर्शाता है। इसके साथ ही अधिकरण ने आदेश को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रमुख कार्मिक विभाग को भेजा है।

सीएमडी पावरग्रिड के.श्रीकांत सम्मानित

जयपुर, (का.सं.)। के. श्रीकांत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को बिजनेस टुडे-पीडब्ल्यूसी इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ (पावर) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

पॉक्सो कोर्ट में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए पीआईएल पेश

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश की पॉक्सो अदालतों में मुकदमों की त्वरित सुनवाई नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। कुणाल रावत की ओर से पेश इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पक्षकार बनाया है। पीआईएल पर सप्ताह के अंत में सुनवाई हो सकती है।

पीआईएल में कहा गया कि प्रदेश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों सहित नाबालिगों के दुष्कर्म मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्थान प्रदेश में दुष्कर्म के अपराध सर्वाधिक हुए हैं और पिछले दो साल के दौरान ही 11307 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हुआ है। इन केसों की सुनवाई के लिए मौजूदा पॉक्सो कोर्ट की संख्या बहुत कम है।

उदयपुर की जघन्य घटना जंगलराज का जीता जागता प्रमाण : राठौड़

> ■ 'कांग्रेस राज में तुष्टिकरण की राजनीति इस कदर चरम पर है कि धर्म का चोला ओढ़कर असामाजिक तत्व समाज में नफरत फैला रहे हैं जो सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है'

जयपुर। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि उदयपुर में मालदास स्ट्रीट स्थित भूत महल के पास युवक की सरेआम निर्मम हत्या एवं सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी व धमकी देने की जघन्य घटना राजस्थान के जंगलराज का जीता जागता प्रमाण है।

राठौड़ ने कहा कि मानवता के दुश्मन बने बैठे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उदयपुर में की गई युवक की हत्या से उपजा तनाव का माहौल चिंताजनक है एवं इस घटना के प्रति लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। इस क्रूरतम अपराध को अंजाम देने वाले प्रदेश के अमन-चैन के दुश्मन है जिनका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के सिम्मी, पीएफआई या अन्य इस्लामिक संगठन के साथ संबंध होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को चाहिये कि वो इन पहलूओं पर भी गहनता से जांच करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले गुनाहगारों को शीघ्र गिरफ्तार करें, पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ रुपये तत्काल मुआवजा राशि दें। कांग्रेस राज में तुष्टिकरण की राजनीति इस कदर चरम पर है कि अब वैचारिक भिन्नता के कारण सरेआम लोगों का गला काटा जा रहा है और धर्म का चोला ओढ़कर असामाजिक तत्व समाज में नफरत फैला रहे हैं जो सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है।

कन्हैयालाल का समझौता कराने आए लोगों से भी पूछताछ होगी

जयपुर । अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि उदयपुर हत्याकांड में मरे कन्हैयालाल के खिलाफ 10 जून को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी डालने का मामला दर्ज कराया गया था।

इस प्रकार के अन्य मामलों की भांति उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत से जमानत पर छूटने के बाद 15 जून को कन्हैया लाल ने थाने में पहुंचकर अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है।

स्थानीय थानाधिकारी ने इस रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद धमकी देने वालों सहित दोनों समुदायों के जिम्मेदार वरिष्ठ लोगों को थाने बुलाया और समझाइश की गई थी। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद आपसी समझौता भी हो गया।

समझौते के बाद कन्हैया लाल अपनी हस्तलिखित रिपोर्ट देकर गए कि हमारा मनमुटाव अब खत्म हो गया है और इस मामले में अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । एडीजी ने बताया कि पुलिस द्वारा समझौता कराने आए व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है।

मिश्र ने निंदा की

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उदयपुर में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय बताया है।

महारानी कॉलेज की छात्राओं ने जेएलएन मार्ग पर जाम लगाया

जयपुर (कासं)। महारानी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को परेशान छात्राओं ने शैक्षिणक कार्य बंद कर राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर सड़क रोककर जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने समझाइश कर मामला शांत करवाया।

प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारी सुरक्षा की मांग को 7 दिन में पूरी नहीं किया तो उठा आंदोलन किया जाएगा। जिसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार होगा। दरअसल, 4 जून को महारानी कॉलेज के बाहर एक युवक द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की गई थी। इसके अगले ही दिन पुलिस ने मनचले युवक को हिरासत में ले लिया। लेकिन इसके बाद युवक फिर से छोड़ दिया गया। वहीं अब युवक का वकील छात्राओं पर समझौते के लिए दबाव बना रहा है। जिसकी वजह से ही कई छात्राओं ने कॉलेज आना तक छोड दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा अब तक छात्राओं की सुरक्षा के लिए न तो गार्ड की व्यवस्था की गई है। और ना ही कैमरे लगाए गए हैं। जिसको लेकर छात्राएं लगातार विरोध कर रही है। प्रदर्शनकारी कोमल ने कहा कि 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है।

कॉन्स्टेबल,पीटीईटी व यूपीसी परीक्षार्थियों को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 की पालना के क्रम मे राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा-2021 व पीटीईटी परीक्षा-2022 एवं यूजीसी नेट परीक्षा के परीक्षार्थियों को साधारण एवं एक्सप्रेस बसों मे नि:शुल्क यात्रा सुविधा के आदेश जारी किये गये है।

राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से सभी मुख्य प्रबन्धको को पाबन्द किया गया है कि राजस्थान पुलिस विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली 2 जुलाई, को पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा-2021 व जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा 3 जुलाई को आयोजित पीटीई एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी, नई दिल्ली द्वारा 8-9 जुलाई एवं 11-12 जुलाई तथा 12-14 अगस्त को अयोजित होने वाली यूजीसी नेट दिसम्बर, 2021 एवं जून, 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों को आने व जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आईडी के आधार पर एक दिवस पूर्व एवं परीक्षा के एक दिवस बाद के लिये नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करावें। परीक्षार्थी के गांव व शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने व वापिस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नही होने पर एक से अधिक कनेक्टींग बस का उपयोग कर सकेंगे।

रामचरण बोहरा ने सासंद निधि से दिव्यांगों को स्कूटी वितरित कीं

जयपुर, (का.सं.)। सांसद रामचरण बोहरा ने सेवा सप्ताह के तहत झुलेलाल मंदिर कंवर नगर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगो में 7 को स्कूटी, 5 को ट्राईसाईकिल, 5 को व्हीलचेयर एवं 2 को बैसाखी, 9 दिव्यांग महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित की। कार्यक्रम के दौरान स्ट्रीट वेण्डर योजना के तहत 51 खाताधारियो में 10 लाख 20 हजार रूपये के ऋण बैक ऑफ बड़ोदा के माध्यम से उपलब्ध करवाने के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 98 खाताधारी बीमा योजना से पंजीकृत हुए।

सांसद बोहरा ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान उक्त सामग्री वितरित करते हुए कहा कि इनको भी अपनी सामान्य जिन्दगी जिने का पूर्ण अधिकार है। स्कुटी, ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर से अपने स्वयं के कामकाज के लिये कहीं भी आ सकेंगे, निर्भरता कम होगी। बोहरा ने मंगोड़ी वालो की बगीची ब्रहमपुरी में जनसंघ से भाजपा तक समर्पण एवं लगन से कार्य करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का प्रशस्ति पत्र, दुपटा एवं शाल ओढ़ाकर सम्मान करते हुए कहा कि देश भर में लाखो कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं लगनशीलता ने भाजपा को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। राष्ट्रवाद की अवधारणा ने हमेशा सक्रिय रहने एवं लोगों के सुख-दुख में शामिल होने की प्रेरणा दी है।

सांसद बोहरा ने जल महल के सामने स्थित बलदेव मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, सहित चांदी की टकसाल चांदपोल चांदपोल स्थित विभिन्न मंदिरो में कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान एवं पूजा अर्चना कर क्षेत्र एवं राष्ट्र के उन्नति की प्रार्थना की एवं परिंदों के लिए परिंडे भी लगाए। इसके पश्चात् पारीक कॉलेज में वृक्षारोपण कर कॉलेज के छात्र-छात्राओं से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम के दौरान संयोजक केदार शर्मा, उपाध्यक्ष जयपुर शहर, पूर्व विधायक हवामहल मोहनलाल गुप्ता, किशनपोल सुरेन्द्र पारीक, मण्डल अध्यक्ष जल महल मण्डल कैलाश जांगिड़, पोड्रिक मण्डल मानसिह देवडा, शास्त्री नगर मण्डल हर्षवर्धन शर्मा, किशनपोल मण्डल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, चांदपोल मण्डल अध्यक्ष हेमन्त चौहान, जोहरी बाजार मण्डल अध्यक्ष हेमन्त चोहान सहित मनोज शर्मा हवामहल, राजेश ताम्बी, कान्ता प्रसाद शर्मा, नवीन सोगानी, वीरेन्द्र शर्मा, पार्षद, और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष अशोक पाण्ड्या ने किया।

सांसद रामचरण बोहरा ने सेवा सप्ताह के तहत झुलेलाल मंदिर कंवर नगर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगों को 7 स्कूटी, 5 ट्राईसाईकिल, 5 व्हीलचेयर, 2 बैसाखी व 9 दिव्यांग महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित कीं।

उदयपुर हत्याकांड के बाद राजधानी जयपुर में भी सुरक्षा बढ़ाई

जयपुर (कासं)। उदयपुर में युवक की हत्या के बाद राजधानी जयपुर में भी पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संभागीय आयुक्त विकास सीतारामजी भाले ने आदेश जारी कर बुधवार शाम साढ़े 5 बजे तक पूरे जयपुर क्षेत्र में इंटरनेट बंद किया है। दूसरी तरफ धर्म गुरूओं ने भी वीडियो संदेश जारी कर लोगों से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील की है।

डीजीपी एम.एल. लाठर के निर्देश के मुताबिक उदयपुर की घटना के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी विशेष निगरानी सुनिश्चित करेंगे। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अगले दो दिन में शांति समिति की बैठक के साथ ही सीएलजी की थानावार बैठकें भी आवश्यक रूप से आयोजित की जाएं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए। अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता हो तो तत्काल उच्च स्तर पर सूचित कर जाब्ता मंगवाएंगे। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। ऐसे लोग किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय से हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे प्रदेश में एक महीने तक धारा-144 तक लागू की गई है।

रेरा कानून की खामियों के कारण लोग, बिल्डरों के आगे बेबस होने को मजबूर?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कानून की खामियों के कारण लोग रकम देकर भी बिल्डरों के आगे बेबस हो रहे है। दरअसल, बिल्डर आर्किटेक्ट के माध्यम से कम्पलीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) रेरा में जमा तो करवा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग का काम एक साल बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा ही मामला एफएस हाउसिंग प्रा. लि. के दुर्गापुरा स्थित 'द क्रस्ट' का है। बिल्डर ने पिछले साल 1 जून को रेरा को कम्पलीशन सर्टिफिकेट दे दिया। इस आधार पर कुछ बुकिंगकर्ताओं ने गृह प्रवेश भी कर लिया, लेकिन मौके पर अब भी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे लोग काम पूरा होने और बिल्डर द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिवास प्रमाण पत्र) लेने का इंतजार कर रहे है। नियमों के तहत इसके बाद ही वे लोग बिल्डिंग में रहने के पात्र होंगे। बिल्डर की इसी खामी के कारण बुकिंगकर्ताओं को पूरी रकम देने के बाद भी आवास के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है।

सूत्रों की मानें तो इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए रेरा 4 बार एक्सटेंशन दे चुका है। जबकि, ज्यादातर अन्य मामलों में अधिकतम 3 बार ही एक्सटेंशन दिया गया। 31 मई, 2021 को एक्सटेंशन खत्म होने से प्रोजेक्ट लेप्स हो गया। प्रमोटर की ओर से चौथी बार एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया गया, लेकिन रेरा ने आवेदन को खारिज कर दिया। बाद में अथॉरिटी ने एक दिन का एक्सटेंशन स्वीकृत किया। इसके पीछे बिल्डर द्वारा औपचारिकता पूरी करने का तर्क दिया गया।

> ■ एफएस हाउसिंग प्रा. लि. के दुर्गापुरा स्थित 'द क्रस्ट' प्रोजेक्ट का बिल्डर ने गत वर्ष 1 जून को कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन मौके पर अभी भी निर्माण कार्य जारी

गंभीर मुद्दा यह है कि रेरा को सर्टिफिकेट के आधार पर मौके पर जांच का अधिकार नहीं है और संबंधित निकाय जांच करने से कतरा रहे है। रेरा के रजिस्ट्रार आर.सी.शर्मा का कहना है कि अथॉरिटी के आदेश के तहत बिल्डर ने पैसा जमा करा दिया। कम्पलीशन सर्टिफिकेट आ गया है, जब जांच संबंधित निकाय करे कि इसमें कोई कमी है या नहीं।